

**ग्रोथ को लेकर
आशावादी हैं
उद्योग जगत**

**-सुकुमार साह-
-राष्ट्रतुट दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जनवरी) केंद्रीय
बजट 2026-27 से पहले भारत के
उद्योग जगत (इंडिया इंक) का रुख देश
की आर्थिक दिशा को लेकर सकारात्मक
बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चित
माहौल के बावजूद, उद्योग जगत के
अधिकारशाली ने निर्णय विकास को
लेकर धरोसा जताया है। यह भ्रम
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिकबो) के प्री-
बजट सर्वेक्षण 2026-27 से उपभूक्त
सामने आई है, जिसमें आगामी बजट से
पहले, उद्योग की अपेक्षाओं और**

- औद्योगिक संगठन फिक्की के प्री बज सर्वे में 80 प्रतिशत उद्योगपतियों ने भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया।

नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।

सर्वेक्षण व्यापक स्तर पर आशावाद को दर्शाता है। लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया है। करीब आधे उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीस डोमेस्टिक प्रोडक्शन-जीडीपी) की वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत के दायरे में बनी रहेगी, जो अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की (शेष पृष्ठ 5 पर)

ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकियां नाकामयाब रही ग्रीनलैंड प्रकरण में

ट्रंप अपने तमाम नाटकीय उद्घोषों के बावजूद यूरोपीय देशों की एकता को नहीं तोड़ पाए और अन्ततोगत्वा टैरिफ बढ़ाने की धमकी वापस ली

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रपति दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 जनवरी। कई हफ्तों की तीखी बयानबाजी के बाद, यूरोप के कई देशों पर टीएफए लगाने की धमकी से राष्ट्रपति डॉल्ड ट्रम्प हट गए। यह उनके ट्रम्पे कार्यकाल की विदेश नीति में एक अहम मोड़ को दर्शाता है। इसका कारण व्यापारिक अशंकाओं नहीं, बल्कि भू-राजनीति थी: प्रोलेनैड और आर्कटिक सुरक्षा पर एक जल्दबाजी में तैयार किया गया भविष्य के समझौते का ढांचा, जिसने नाटो के महासचिव मार्क रूटे की मध्यस्थता से तैयार किया गया। यह प्रकरण ट्रम्प की दबाव-आधारित कूटनीति की हदों, यूरोप की सामूहिक शक्ति के मजबूती और उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्वर्धनों को उजागर करता है।

ट्रम्प चाहते हैं कि उनका रुख परिवर्तन रणनीतिक कदम लगे, और यहाँ तक कि वे विजयी लगे। टैरिफ निलंबित कर वे लचीलापन दिखाते हैं, पर ग्रीनलैंड का हवाला देकर वे खुद की

- ट्रंप अपने प्रथम कार्यकाल से ही यह सनक भरी शिकायत करते रहे हैं कि अमेरिका को नाटो से मिलता ही क्या है, केवल यूरोप की सुरक्षा प्रदान करने का बोझ।
- पर, अब ट्रंप को ग्रीनलैंड के मसले पर, नाटो की “शरण” में जाना पड़ा और नाटो के सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से एक “फेमवर्क” निकालना पड़ा।
- ट्रंप डार्वोस सम्मेलन में एक घंटे के भाषण से विश्व में अमेरिका के प्रभुत्व को जताना चाहते थे, पर, उनके भाषण में केवल रीति-नीति के विरोधाभासी तर्क ही उजागर हुए।
- और अंत में उन्हें मंच से कहना पड़ा, अमेरिका का मकसद सारे प्रकरण में विश्व की सुरक्षा थी, न कि ग्रीनलैंड की खनिज सम्पदा को हड़पना।
- इस ग्रीनलैंड प्रकरण ने यह भी उजागर किया, अन्य देशों की एकता व संयम ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं।

सुरक्षा को लेकर जुनूनी, कठोर लेकिन घटनाक्रम और समयक्रम कुछ यथार्थवादी के रूप में पेश करते हैं। (शेष पृष्ठ 5 पर)

**‘एआई जॉब
मार्केट को
तेजी से बदल
रहा है’**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रपुत्र दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, २१ (मजबूत) वाइए
काँफर कर्मचारियों (जेनरल मैट या
बौद्धिक कार्य करने वाले) के लिए एक
बड़ा बदलाव आने वाला है। बिल गेट्स
का कहना है कि सरकारें इसके लिए
तैयार नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह-
संस्थापक ने दावोस में आयोजित
अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में चेतावनी
दी कि आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस
(एआई) अपेक्षा से कहीं तेजी से
नौकरी-बाज़ार को नया आकार देने जा

■ बिल गेट्स ने दावोस में चेतावनी देते हुए कहा कि यह जरूरत से ज्यादा तेजी से हो रहा है और इसका असर बौद्धिक कार्य वाली नौकरियों पर पड़ेगा।

रही है, और तैयारी के लिए समय बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है।

बीमारी के इलाज से लेकर शिक्षा तक में एंटी को संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, गेट्स ने चेतावनी दी। यदि इसे सही ढंग से प्रबंधित (मैनेज्ड) नहीं किया गया, तो कार्यबल, भर्ती के पैटर्न और आर्थिक न्याय पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है।

उनके अनुसार, इन चुनौतियों की (शेष पृष्ठ 5 पर)

मध्य प्रदेश का शहर, धार पुलिस छावनी बना

**8,000 पुलिसकर्मी, जिनमें सीआरपीएफ रैपिड
एक्शन फोर्स आदि तैनात किये गए**

- मसला था, भोजशाला, ग्यारहवीं शताब्दी के वाग् देवी (सरस्वती देवी) के मंदिर में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने का न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार।
- इस स्थल को मुसलमान कमाल मौला की मस्जिद मानते हैं।
- न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार, हिंदू बसंत पंचमी को प्रातःकाल से सूर्यास्त तक अपनी पूजा-अर्चना कर सकते हैं तथा मुसलमान शुक्रवार के दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नमाज़ अदा कर सकते हैं।
- पर, न्यायालय की व्यवस्था में, इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि जब बसंत पंचमी, शुक्रवार को पड़े, जैसा 23 जनवरी को है, तब क्या किया जाए।
- प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, उन लोगों की लिस्ट मांगी गई है, जो शुक्रवार को वहाँ नमाज़ अदा करने जाना चाहते हैं। पुलिस पैदल और वाहनों में लगातार पैट्रोलिंग कर रही है और सीसीटीवी के मार्फत चौकसी बरत रही है तथा सोशल मीडिया के गतिविधि पर भी निगाह रखे हुए है।

की गई थी।

यह आवेदन 2 जनवरी को एच
एफ जे की ओर से अधिवक्ता विष्णु
शंकर जैन द्वारा दायर किया गया था और
इसे तत्काल सुनवाई के लिए अदालत
के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याचिका

मैं कहा गया था कि “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण” का 2003 का आदेश उन परिस्थितियों को संबोधित नहीं करता, जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज़ के साथ पड़ती है।
(शेष पृष्ठ 5 पर)